

करोड़ रुपए (उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं है) खर्च किए गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान रद्दी बेल्टों की बिक्री से लगभग एक करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Income tax raids

1346. SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there have been a number of raids by income-tax and other tax authorities recently; and

(b) if so, what is the extent of success achieved in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) During first three months of 1985, Income-tax Department conducted 1356 searches resulting in seizures of *prima facie* unaccounted assets valued at Rs. 7.75 crores approximately. Drive against evasion of excise duty has been intensified and as per latest reports during January—March, 1985, 1650 cases were detected involving an estimated amount of excise duty of Rs. 45.83 crores. Customs searches were conducted for detection of undervaluation and consequent evasion of duty to the extent of Rs. 21.39 crores approximately, in cases other than purely smuggling.

“टेलको” तथा “टिस्को” द्वारा रद्दी लोहे की बिक्री

1347. श्री हुसमदेव नारायण यादव: क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जमशेदपुर स्थित “टेलको” तथा “टिस्को” नामक कंपनियाँ रद्दी लोहा बेच देती हैं; यदि हाँ, तो उन व्यापारियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान यह लोहा बेचा गया है और

इन्हें किन-किन दरों पर कितना लोहा बेचा गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि रद्दी लोहे के नाम में इस्पात बेचा जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त माल पश्चिमी बंगाल के रास्ते बंगलादेश पहुँच जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह): (क) और (ख) रद्दी लोहे के मूल्यों तथा वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा इस प्रकार के लोहे की बिक्री से सम्बन्धित जानकारी सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर ख़ादी आएगी।

Grant of loan under the self Employment scheme

1348. SHRI BISWA GOSWAMI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry ordered in March, 1983 to disburse Rs. 200 crores directly under the self-employment scheme;

(b) whether it is also a fact that the applications of the prospective applicants duly screened by the District Industries Centre were rejected by the nationalised banks;

(c) whether it is also a fact that Rs. 25,000/- under the scheme per person were advanced without collateral security from the applicants which were forwarded to the bank directly without screening by the District Industries Centre; and

(d) if so, what are the details thereof?